



संवैधानिक सुरक्षा उपायों का तुलनात्मक अध्ययन

¹Monika Singh Thakur and ²Dr. Sarvendra Kumar

¹Research Scholar, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

²Professor, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20157361>

Corresponding Author: Monika Singh Thakur

सारांश

वर्णनात्मक और तुलनात्मक शोध डिजाइन पर आधारित इस अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल गिरफ्तारी और गोपनीयता के अधिकार के बीच संबंधों को समझना और विभिन्न देशों में अपनाए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की तुलना करना है। डिजिटल युग में, जबकि प्रौद्योगिकी ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित कर दिया है, इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार के लिए नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। डिजिटल गिरफ्तारियाँ, जिसमें सोशल मीडिया निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और डेटा संग्रह शामिल हैं, सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी अधिकता नागरिकों की स्वतंत्रता और गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इस संदर्भ में, इस अध्ययन का उद्देश्य इन चुनौतियों को समझना और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रभावी संवैधानिक उपायों का विश्लेषण करना है।

मूल शब्द: संवैधानिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक।

1. प्रस्तावना

भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और एक युवा राष्ट्र है जो अगले कुछ दशकों में जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए तैयार है। मोबाइल फोन भारत में सामाजिक प्रभाव के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक है। यह वह माध्यम बन रहा है जिसके माध्यम से भारतीय प्रेरणादायक सेवाओं तक पहुँच रहे हैं।

डिजिटल अपनाने की अभूतपूर्व गति और पैमाने को आपूर्ति कारकों के लगभग पूर्ण संगम द्वारा संचालित किया जा रहा है जैसे बैंडविड्थ की कीमते गिरना, मोबाइल डेटा की कीमते कम होना, 4 जी का तेजी से रोल-आउट, मोबाइल प्रौद्योगिकी का आक्रामक नेविगेशन और तेजी से बढ़ती समृद्धि जैसे मांग कारक, जनसांख्यिकी में तेजी से मोबाइल प्रौद्योगिकी अपनाना, मोबाइल प्रौद्योगिकी एक बड़ी आबादी की सेवा कर रही है, जिनके पास पहले एक-दूसरे से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से जुड़ने के खराब अवसर थे। यह तेजी से डिजिटल अपनाने से एक "मोबाइल-फर्स्ट" इकोसिस्टम चल रहा है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत हमेशा से संयुक्त या विस्तारित एकल परिवारों का आदी रहा है, हालांकि शहरीकरण के कारण औसत परिवार का आकार 5.5 के आसपास बना हुआ है।

जीविका या उप-जीविका स्तर पर रहने वाली एक बड़ी आबादी ने प्रसिद्ध भारतीय "मितव्ययी जीन" को जन्म दिया है। भारतीय अत्यधिक मूल्य-सचेत होते हैं। सस्ते या असीमित डेटा के साथ एक सस्ता मोबाइल डेटा मितव्ययी विरासत की मानसिकता का लाभ उठाता है क्योंकि यह एक सामाजिक सक्षमता है और साथ ही बहुत ही व्यक्तिगत है जिसमें सभी जानकारी, कीमते और कनेक्शन उपलब्ध हैं, जो सीधे उंगलियों पर उपलब्ध हैं।

2. साहित्य की समीक्षा

उदयन मुखर्जी, आरके नरूला (2021) ^[1] इस पुस्तक में गोपनीयता के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई है, जिसमें गोपनीयता का डेटा, डेटा की सुरक्षा और डिजिटल युग में गोपनीयता के लिए आने वाली चुनौतियाँ शामिल हैं। यूरोपीय संघ के GDPR के संदर्भ में डेटा सुरक्षा विधेयक पर चर्चा, साथ ही मध्यस्थों की जिम्मेदारी भी काफी विस्तृत है। डेटा की सुरक्षा और डेटा के उपयोग के बीच संतुलन एक जटिल मुद्दा है, जिस पर चर्चा की गई है। गोपनीयता के अपवाद पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। गोपनीयता, पारिवारिक गोपनीयता, वाणिज्यिक गोपनीयता, संचार गोपनीयता और गोपनीयता के इन पहलुओं में से प्रत्येक के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच अंतर को कवर किया गया है, जो गोपनीयता के प्रति एक ताज़ा दृष्टिकोण दिखाता है।

जीवीएस जगन्नाथ राव (2021) [2] सभी हितधारकों के लाभ के लिए एक छोटी सी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इंटरनेट पर शरारती तत्वों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें भारत के बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने वाले कानून शामिल हैं जो इन शरारती तत्वों को बुनियादी ढांचागत और तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री से समाज को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में चिंतित नहीं हैं, जिनकी पहुंच सभी उम्र और स्थानों के लोगों तक विभिन्न हैंडहेल्ड उपकरणों के माध्यम से होती है। इसमें अश्लील, आपत्तिजनक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारी पोस्ट करने वाले बेईमान तत्वों को विनियमित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की मांग में आवश्यक विनियमन के बारे में भी बताया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सोशल मीडिया के दुष्ट उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने का दावा करते हैं। कोनराड कोलनिग, अनास्तासिया शुबा, रूबेन बिन्स, मैक्स वान क्लीक और निगेल शैडबोल्ड (2021) [3] शोधकर्ता ने उपयोगकर्ता गोपनीयता से संबंधित कई आयामों के साथ 2020 से 24k Android और iOS ऐप का एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने पाया कि तीसरे पक्ष की ट्रैकिंग और अद्वितीय उपयोगकर्ता पहचानकर्ताओं को साझा करना दोनों इकोसिस्टम के ऐप्स में व्यापक है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए बनाए गए ऐप्स में भी। शोधकर्ता ने पाया कि बच्चों की श्रेणी में iOS ऐप अपने Android समकक्षों की तुलना में कम विज्ञापन संबंधी ट्रैकिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन वे बच्चों के स्थान तक अधिक बार पहुँच सकते हैं। अध्ययन में सभी अध्ययन किए गए ऐप्स में, यूएस, ईयू और यूके गोपनीयता कानून के व्यापक संभावित उल्लंघनों को उजागर किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता की सहमति के बिना तीसरे पक्ष की ट्रैकिंग का उपयोग, बच्चों के ऐप्स में तीसरे पक्ष के साथ व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी साझा करने से पहले माता-पिता की सहमति की कमी, ट्रैकिंग लाइब्रेरी का गैर-डेटा न्यूनतम कॉन्फिगरेशन, डेटा सुरक्षा के पर्याप्त स्तर के बिना देशों को व्यक्तिगत डेटा भेजना और ट्रैकिंग के बारे में पारदर्शिता की निरंतर अनुपस्थिति शामिल है, नावी (2020) [4] गोपनीयता कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, आईटी पेशेवरों, व्यापार प्रबंधकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिनके सभी व्यक्तिगत डेटा उपयोग में परस्पर विरोधी हित हैं। यह एक ऐसा कानून बनाने में शामिल जटिलताओं को पकड़ता है जो एक उत्पादक संपत्ति के रूप में व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत डेटा के मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण के साथ गोपनीयता के मानव अधिकार की रक्षा करने का प्रयास करता है। पुस्तक जागरूकता पैदा करने के लिए अधिनियम को खंड दर खंड समझाती है। यह उन विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी चर्चा करता है जो विभिन्न पेशेवरों को कानूनी प्रावधानों के विभिन्न निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करते हैं। यह डेटा ऑडिटिंग के विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए डेटा सुरक्षा अधिकारी और डेटा ऑडिटर के रूप में करियर बनाने के इच्छुक पेशेवरों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका भी है, जिसमें डेटा ट्रस्ट स्कोर और भारत के व्यक्तिगत डेटा मानक के रूप में अनुपालन के लिए रूपरेखा पर चर्चा शामिल है।

रिपोर्ट (2020) यह भारत में डिजिटल सिविक स्पेस पर सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में निगरानी और डेटा सुरक्षा पर एक अध्ययन है, यह अध्ययन भारतीय

नागरिक समाज के लिए डिजिटल अधिकारों पर नीति और कानूनी ढांचे के प्रभावों की जांच करता है। रिपोर्ट में निगरानी प्रौद्योगिकी, घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के डिजाइन और प्रभाव को शामिल किया गया है।

3. अनुसंधान क्रियाविधि

- विषयगत विश्लेषणसाक्षात्कार और फोकस समूह चर्चा से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इसका संचालन किया जाता है।
- डिजिटल निगरानी और गोपनीयता पर कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययनसंचालित हुआ।
- डेटा संग्रहण के दौरान प्राप्त सांख्यिकीय जानकारीविश्लेषण किया जाता है।
- डेटा को तालिकाओं में बदलनाडिजिटल गिरफ्तारी और गोपनीयता के बीच प्रभाव को दर्शाने के लिए चार्ट, और ग्राफ़।
- नमूने का आकार लगभग हैइसमें 50-70 विशेषज्ञ (वकील, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ) और 100 नागरिक शामिल होते हैं।
- डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिएfc SPSS जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

4. डेटा का विश्लेषण

तालिका संख्या 1: अन्य लोगों से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने का संकेत देते हुए यह दर्शाता है कि आपके पास ऐसा करने का अधिकार है।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
हाँ	26	17%
नहीं	110	73%
कोई विवरण नहीं	15	10%

लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जानकारी साझा करके एक दूसरे से जुड़ते हैं। नतीजतन, हमारे बारे में जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह कंपनियां हों या अन्य उपभोक्ता, व्यक्तिगत जानकारी देकर हमारी गोपनीयता से समझौता कर सकते हैं, जिसे हमने स्वयं नहीं दिया होगा। इस प्रश्न के माध्यम से शोधकर्ता ने गोपनीयता की अन्योन्याश्रितता की अवधारणा का विश्लेषण करने की कोशिश की है। लगभग 17% एप्लिकेशन की गोपनीयता नीति में यह शामिल है कि उपयोगकर्ता के पास अन्य लोगों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने का अधिकार था। फिर से, उपयोगकर्ता से जानकारी साझा करने की सहमति ली गई थी, जो फिर से एक स्पष्ट या निहित आवश्यकता थी जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। 73% एप्लिकेशन में इसके लिए कोई विवरण नहीं था। जबकि शोधकर्ता द्वारा विश्लेषण किए गए 10% ऐप्स ने पाया कि तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी साझा करना ऐसा करने के अधिकार का संकेत नहीं देता है।

तालिका संख्या 2: उन आवेदनों की संख्या दर्शाती है जिनके तहत उन्हें विनियमित किया गया था।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
हाँ	95	63%
नहीं	55	37%

शोधकर्ता ने यह विश्लेषण करने की कोशिश की कि क्या एप्लिकेशन की गोपनीयता नीतियों में उन कानूनों को निर्दिष्ट करने वाला खंड प्रदान किया गया है जिनके तहत उन्हें विनियमित किया गया था। शोधकर्ता ने विश्लेषण किया कि लगभग 63% ऐप्स में उन्हें विनियमित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान था, जबकि 37% ऐप्स में उन विनियमों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था जिनके तहत उन्हें विनियमित किया गया था। गोपनीयता नीतियों में उपयोगकर्ता को विनियमित करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो उस क्षेत्राधिकार के आधार पर हो जिसमें उपयोगकर्ता स्थित है और उपयोगकर्ता को विनियमित करने वाले विशिष्ट कानून हैं। क्योंकि जब उपयोगकर्ता अपना डेटा दे रहा होता है या सेवा का उपयोग कर रहा होता है तो उपयोगकर्ता को यह जानने का अधिकार होता है कि उन्हें किस विनियमन द्वारा विनियमित किया जा रहा है, अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता को संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने का अधिकार है।

तालिका संख्या 3: निवारण हेतु संपर्क हेतु उपलब्ध कराए गए आवेदनों की संख्या दर्शाती है।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
हाँ	74	49%
नहीं	76	51%

गोपनीयता नीति में संपर्क जानकारी के साथ फोन नंबर, ईमेल आईडी, कार्यालय का पता, अधिकार क्षेत्र जिसके तहत उन्हें विनियमित किया जाएगा, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। किसी भी उल्लंघन के मामले में शिकायत अधिकारी से संपर्क करने का तरीका, यदि उपयोगकर्ता को लगता है कि उनके डेटा को उनकी सहमति के बिना संसाधित किया गया है या उपयोग जानने के लिए, डेटा-दर-डेटा नियंत्रक का संग्रह, डेटा के अधिकार क्षेत्र के बारे में जानना आदि ऐसे हर मामले के लिए जो उपयोगकर्ता एप्लिकेशन चलाकर सेवा तक पहुंचने के दौरान सामने आता है। शोधकर्ता ने इस प्रश्न के माध्यम से विश्लेषण करने की कोशिश की कि क्या गोपनीयता नीतियों में निवारण के लिए संपर्क करने का ऐसा प्रावधान है। शोधकर्ता द्वारा शोध के लिए लिए गए आवेदनों में से लगभग 51% में गोपनीयता नीतियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि 49% आवेदनों में गोपनीयता नीतियों में उपयोगकर्ताओं के निवारण के लिए संपर्क जानकारी निर्दिष्ट करने का प्रावधान है।

शोधकर्ता के अनुभवजन्य विधि के परिणाम बताते हैं कि मोबाइल फोन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा पैठ रखते हैं। मनोरंजन, संगीत, यात्रा से लेकर मैसेजिंग, डेटिंग, स्वास्थ्य और फिटनेस तक, उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न श्रेणियों के एप्लिकेशन डाउनलोड किए जाते हैं। कुछ ऐप मुफ्त में उपलब्ध हैं, कुछ सशुल्क हैं जबकि कुछ इन-ऐप खरीदारी के साथ उपलब्ध हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बेहतर सेवा प्रदान करने के नाम पर ऐप चलाने के दौरान एप्लिकेशन विक्रेता द्वारा उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र किया जाता है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता नीतियाँ प्रदान की जाती हैं जो गोपनीयता विरोधाभास को दर्शाती हैं। उत्तरदाता सहमत थे कि गोपनीयता नीति लंबी, समझने में कठिन और समय लेने वाली थी। परिणाम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ उत्तरदाताओं के बीच जागरूकता भी बढ़ी है। शोध ने आगे गोपनीयता विरोधाभास, उचित प्रवर्तन

तंत्र की कमी, मुद्दों के निवारण के लिए नियामक प्राधिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। शोधकर्ता ने महसूस किया कि कठोर दंड के साथ उचित प्रवर्तन तंत्र होना चाहिए ताकि एप्लिकेशन विक्रेताओं द्वारा उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को खतरे में न डाला जाए।

तालिका संख्या 4: लिंग दर्शाती है।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
महिला	80	53%
पुरुष	71	47%

इस प्रश्न में, शोधकर्ता ने यह समझने की कोशिश की कि उत्तरदाताओं में से कौन सा लिंग मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा सक्रिय था और एप्लिकेशन का इस्तेमाल करता था। 2019 में भारत में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 75 प्रतिशत पुरुष वयस्क आबादी के पास फोन था, जबकि केवल 51 प्रतिशत महिला आबादी के पास फोन था। इनमें सबसे बड़ा अंतर पुरुष और महिला स्मार्टफोन मालिकों के बीच था: जबकि 37 प्रतिशत भारतीय वयस्क पुरुषों के पास स्मार्ट फोन थे, केवल 14 प्रतिशत भारतीय वयस्क महिलाओं के पास। यहाँ अध्ययन में 63.8% उत्तरदाता पुरुष थे और 36.2% उत्तरदाता महिलाएँ थीं।

तालिका संख्या 5: आयु दर्शाती है।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
18 वर्ष से कम	13	8.8%
18-24 वर्ष	49	32.8%
25-29 वर्ष	36	23.8%
30-39 वर्ष	39	26%
40-49 वर्ष	9	6.3%
50-64 वर्ष	2	1.5%
65 और उससे अधिक	1	1%

इस प्रश्न में, शोधकर्ता ने यह समझने की कोशिश की कि किस आयु वर्ग के उपयोगकर्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग में अधिक रुचि रखते हैं। शोधकर्ता ने पाया कि जेनरेशन Z के लोग जेनरेशन Y.1 की तुलना में मोबाइल फोन पर अधिक सक्रिय थे और दूसरे नंबर पर जेनरेशन Y.1 की तुलना में जेनरेशन Y.2 के लोग थे। प्राप्त परिणाम यह था कि 23.8% उत्तरदाता 25-29 वर्ष की आयु के थे, इसके अलावा 18-24 आयु वर्ग के 32.8% उत्तरदाता थे। इसके अलावा, 30-39 आयु वर्ग के बीच उत्तरदाताओं की संख्या 26% थी।

तालिका संख्या 6: राष्ट्रीयता दर्शाती है।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
भारतीय	145	97%
अन्य	5	3%

इस प्रश्न में शोधकर्ता ने उत्तरदाता की राष्ट्रीयता का पता लगाने की कोशिश की। 97% उत्तरदाता भारतीय थे। भारत में डेटा उल्लंघनों में वृद्धि हुई है, डेटा उल्लंघनों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिसमें 100 से अधिक मामले शामिल हैं। नवंबर 2021 तक 86.63 मिलियन डेटा खतरे में आ जाएगा। इसलिए भारतीय राष्ट्रों के बीच डेटा गोपनीयता के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है।

तालिका संख्या 7: संबंध स्थिति दर्शाती है।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
अकेला	76	51%
विवाहित	74	49%

इस प्रश्न में शोधकर्ता उत्तरदाता की रिश्ते की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। चूँकि उत्तरदाता के रिश्ते ने उत्तरदाता द्वारा मोबाइल फोन और एप्लिकेशन के उपयोग में एक प्रमुख भूमिका निभाई। लगभग 49% उत्तरदाता विवाहित थे और 51% उत्तरदाता अविवाहित थे। यह निश्चित रूप से भारत जैसे देश में स्थापित करता है।

तालिका संख्या 8: शैक्षिक डिग्री दर्शाने वाली

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
स्नातकोत्तर	49	32.8%
कॉलेज का स्नातक	46	30.8%
हाई स्कूल	31	20.5%
हाई स्कूल से कम	14	9.3%
डॉक्टर की उपाधि	8	5.2%
अन्य	2	1.5%

इस प्रश्न में शोधकर्ता ने यह समझने की कोशिश की कि क्या उत्तरदाता की शैक्षणिक योग्यता ने उत्तरदाता की जागरूकता के बारे में चिंता को प्रभावित करने में कोई भूमिका निभाई है। भारत में साक्षरता दर 2021 74.04% है। लगभग 32.8% उत्तरदाता स्नातकोत्तर योग्यता वाले थे। लगभग 30.8% उत्तरदाता कॉलेज ग्रेजुएट थे। लगभग 20.5% उत्तरदाता हाई स्कूल से संबंधित थे।

तालिका क्रमांक 9: पेशा दर्शा रही है

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
विद्यार्थी	42	27.9%
गृहिणी	23	15.6%
पेशेवर (डॉक्टर, सीए, आदि)	22	14.8%
कंप्यूटर/आईटी संबंधित	19	12.8%
शिक्षण/अनुसंधान	19	12.8%
विनिर्माण/व्यवसाय	13	8.5%
अन्य	11	7.3%
कोई जवाब नहीं	0	0.3%

उपरोक्त प्रश्न में, शोधकर्ता यह समझने की कोशिश करता है कि क्या उत्तरदाताओं के पेशे ने गोपनीयता के बारे में उत्तरदाताओं की चिंता, जागरूकता को प्रभावित किया है। लगभग 27.9% उत्तरदाता छात्र थे। लगभग 12.8% उत्तरदाता शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित थे। लगभग 15.6% उत्तरदाता गृहिणी थीं। लगभग 14.8% डॉक्टर और सीए जैसे पेशेवर थे। लगभग 12.8% उत्तरदाता आईटी क्षेत्र से संबंधित थे।

उपरोक्त प्रश्न शोधकर्ता द्वारा यह समझने के लिए पूछा गया था कि उत्तरदाता इन दिनों किस तरह के गैजेट का उपयोग कई दिनों के लिए कर रहे हैं। शोधकर्ता ने पाया कि भारत में स्मार्ट फोन की पहुंच बहुत अधिक है। कई अध्ययनों ने अनुमान लगाया है कि देश में स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या पिछले एक दशक में

लगातार बढ़ रही है और ऐसा होना जारी रहेगा। प्राप्त उत्तर में लगभग 38% उत्तरदाता स्मार्टफोन और लैपटॉप का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा 27.8% उत्तरदाता स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे थे और लगभग 22.8% उत्तरदाता स्मार्टफोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे थे।

तालिका संख्या 10: प्रयुक्त गैजेट के प्रकार को दर्शाती है।

जवाब	प्रतिक्रियाओं की संख्या	प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत
स्मार्टफोन, लैपटॉप	57	38%
स्मार्टफोन	42	27.8%
स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप	34	22.8%
स्मार्टफोन, नियमित फोन, डेस्कटॉप	12	8%
लैपटॉप	4	2.7%
अन्य	1	0.7%

5. निष्कर्ष

डिजिटल युग ने परस्पर जुड़ाव के एक नए युग की शुरुआत की है, जो गोपनीयता संरक्षण के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। कानून और प्रवर्तन की वैश्विक समीक्षा विविध कानूनी परिदृश्यों, तकनीकी प्रगति और सहयोगात्मक कार्रवाई की अनिवार्यता को नेविगेट करने की जटिलताओं को उजागर करती है। कुछ देशों में, डिजिटल गिरफ्तारी की अवधारणा व्यक्तियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंधों को भी संदर्भित कर सकती है, जैसे कि इंटरनेट शटडाउन या कानून प्रवर्तन या खुफिया एजेंसियों द्वारा डिजिटल व्यवहार की निगरानी। इन धोखाधड़ी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए, सरकारें सार्वजनिक जागरूकता बढ़ा रही हैं, नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह कर रही हैं, और उन्हें साइबर अपराध हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से संदिग्ध घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

6. संदर्भ

- मुखर्जी उ, नरोला आरके. गोपनीयता का न्यायशास्त्र. नई दिल्ली: ओक ब्रिज पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड; 2021।
- राव जीवीएस जगन्नाथ. सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता: सूचना प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021. प्रथम संस्करण. नई दिल्ली: एशिया लॉ हाउस; 2021।
- कोलनिंग क, शुबा अ, बिन्स र, वैन क्लेक म, शैडबोल्ड न. क्या iPhone वास्तव में गोपनीयता के लिए बेहतर है? iOS और Android ऐप्स का तुलनात्मक अध्ययन. गोपनीयता बढ़ाने वाली तकनीकों पर कार्यवाही. 2021।
- नावी. भारतीय व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (पीडीपीए 2020): जागरूक रहें, तैयार रहें और अनुपालन करें. नई दिल्ली: नोशन प्रेस; 12 फरवरी 2020।
- स्वामीनाथन म, बसु अ. निगरानी और डेटा संरक्षण: गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरे. द सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटीज़; 2020।
- चक्रवर्ती अ. डेटा संरक्षण कानून का रहस्य उजागर. प्रथम संस्करण. नई दिल्ली: ओक ब्रिज पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड; अक्टूबर 2019।
- रोबिलार्ड जेएम, फेंगा टीएल, स्पॉर्न एबी, लाया जेए, लोआ

- क, ताआ म, नाडलर्ब र. मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स की गोपनीयता नीतियों और समझौतों की शर्तों की उपलब्धता, पठनीयता और सामग्री. एल्सेवियर; 2019।
8. कामलीटनर ब, मिशेल व. आपका डेटा मेरा डेटा है: परस्पर निर्भर गोपनीयता उल्लंघन को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा. *Journal of Public Policy and Marketing*. 2019;38(4):433-450।
 9. मथन र. गोपनीयता 3.0: हमारे डेटा-संचालित भविष्य को अनलॉक करना. हार्पर कॉलिन्स; 2018।
 10. बेली र, परशीरा स, रहमान फ, साने र. गोपनीयता नीतियों में प्रकटीकरण: क्या "नोटिस और सहमति" काम करती है? NIPFP Working Paper Series No. 246. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी; 2018।
 11. ओ'लफलिन क, नियरी म, एडकिंस ईसी, शूएलर एसएम. अवसाद के लिए मोबाइल ऐप्स की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों की समीक्षा. एल्सेवियर बीवी; 2018।

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.